ally the listed medicines are available in the Ayurvedic dispensaries/units. However, if any medicine is not available in the dispensary the same is made available through the local chemist by the Incharge of the dispensaries/Units. The need for courtsey has been empleasized to the dispensary staff.

(c) and (d) The dispensaries/hospitals/units submit regular monthly indent of medicines as per requirement to the Midical Store Depot which supplies the medicine within four-five days. For this purpose a scheduled programme for submission of regular indents is circulated to all the dispensaries/hospitals/units well in advance.

लघु उद्योगों को दी गयी रियायतों का प्रभाव

382. **श्री रामजी लाल:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति का पालन करते हुए लघु उद्योगों को दी गई रियायतों से उन्हें वर्ष 1991 से हुए फायदे/नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) सरकार की उदार नीति के तहत 1991 से लघु उद्योगों को छूट आदि के माध्यम से निम्नलिखित लाभ प्रदान किये गये हैं:—

(1) लघु उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा करने के लिए स्थापना स्थल संबंधी मानदण्ड को समाप्त किया गया है।

(2) भूमि तथा भवन को छोड़कर, 5 लाख रुपये तक की स्थायी परिसंपत्तियों में पूंजी निवेश वाले लघु उद्योग सेवा व व्यावसायिक उद्यमों से संबंधित उद्योगों को लघु उद्योग के बराबर का दर्जा दिया गया है।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिबंधित सूची को समाप्त किया गया है।

(4) लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए जल तथा वायु-प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत अनुमति लेने की कार्यपद्धति को सरल बनाया गया है अब लघु औद्योगिक इकाइयों को केवल एक रसीद (एक्नोलेमेंट) प्राप्त करनी होती है जिसे स्वीकृति के रूप में माना जाता है, लेकिन इसमें 17 अत्यधिक प्रदूषणकारी क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

5. लघु औद्योगिक इकाइयों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों को 24% तक इक्विटी भागीदारी करने की अनुमति दी गई है।

6. लघु तथा अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को निलंबित भुगतानों पर ब्याज से संबंधित एक अधिनियम की घोषणा अप्रैल, 1993 में की गई।

7. लघु औद्योगिक इकाइयों के अनंतिम तथा स्थाई पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्रों को सरल बनाया गया और अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

7. लघु औद्योगिक इकाइयों के हित में कई उत्पाद-शुल्क कार्य पद्धतियों को सरल बनाया गया है। लघु उद्योग उत्पादन शुल्क छूट योजना के तहत लाभ लेने के लिए अब उद्योग निदेशालय में पंजीकरण कराने की कोई आवश्कता नहीं। लघु औद्योगिक इकाइयों के निजी रिकार्ड उत्पादन शुल्क प्रयोजनों के लिए मान्य होंगे और लघु औद्योगिक इकाइयों को और कोई अतिरिक्त रिकार्ड नहीं रखना है। लघु औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद-शुल्क कार्यालय में कोई मासिक विवरणी नहीं भेजनी है। केवल तिमाही विवरणी ही पर्याप्त है। यदि वस्तुओं की बिक्री 30 लाख रुपये के अंदर हो तो केन्द्रीय आबकारी विभाग में कोई घोषणापत्र दायर नहीं करना है। छूटों से कोई हानि होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

Repeated incidents of food Poisoning

383. **SHRI GHUFRAN AZAM:** Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

SEC-7A